



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 भाद्र 1938 (श0)
(सं0 पटना 754) पटना, शुक्रवार, 16 सितम्बर 2016

सं0 विज्ञा0(4)01-02/2016-01/सू0ज0स0वि0
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग

संकल्प

12 सितम्बर 2016

विषय— बिहार विज्ञापन नीति, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।

1. प्रस्तावना—

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को बिहार कार्यपालिका नियमावली तथा बिहार विज्ञापन नीति, 2008 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं सरकार के विभिन्न निगम/निकाय/समिति/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/प्राधिकार के कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों पर आधारित वर्गीकृत विज्ञापनों, निविदा, सूचनाओं तथा अन्य सामग्रियों को विज्ञापन के रूप में महत्वपूर्ण समाचार पत्र-पत्रिका, आकाशवाणी, दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंटरनेट आदि एवं राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण समाचार-पत्र/पत्रिकाओं में भी विज्ञापन निर्गम तथा केन्द्रीकृत रूप से इसका भुगतान एवं अनुश्रवण करने का दायित्व दिया गया है।

बदलते हुए परिवेश, नई सूचना तकनीक विकसित होने, बदलती हुई कार्य प्रकृति, प्रक्रिया, विभिन्न मुद्दों पर आम नागरिकों का मूड, परसेप्शन, फीड बैक को जानने-समझने, उनकी प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया प्राप्त करने, सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार करने, प्रभावकारी लोक संवाद की स्थापना एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु विभिन्न माध्यमों का पेशेवर तरीके से उपयोग करने, सोशल मीडिया यथा फेसबुक, ट्वीटर, युट्यूब एवं आउटडोर पब्लिसिटी सहित अन्य माध्यमों से विज्ञापन का प्रचार-प्रसार कराने, विज्ञापन सामग्रियों के निर्माण एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सोसाईटी के गठन एवं वित्तीय शक्ति आदि की पृष्ठभूमि में आवश्यकतानुसार कतिपय संशोधन आवश्यक हो जाने एवं बिहार विज्ञापन नीति, 2008 में ऐसे कतिपय प्रावधान समाहित नहीं रहने के कारण वर्तमान परिवेश में विभागीय दायित्वों के निर्वहन हेतु एक नये स्वरूप में विज्ञापन नीति आवश्यक प्रतीत होती है।

अतः तत्संबंधी विद्यमान विज्ञापन नीति के उपबंधों एवं नियमों को अवक्रमित करते हुए सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार द्वारा नई “बिहार विज्ञापन नीति, 2016” गठित किया जाता है।

2.

- (1) यह नीति “बिहार विज्ञापन नीति, 2016” कही जायेगी।
- (2) यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उद्देश्य I—

- (i) विभिन्न मुद्दों पर आम नागरिकों का मूड, परसेप्शन ग्रीड बैंक को जानना-समझना, उनकी प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया प्राप्त करना, और मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों का विश्लेषण कर, आवश्यकतानुसार, सरकारी पक्ष/दृष्टिकोण को त्वरित ढंग से मीडिया के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रस्तुत करने के लिए व्यवस्था करना।
- (ii) सरकार की नीतियों/कार्यक्रमों/उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार, प्रभावकारी लोक संवाद की स्थापना एवं ब्रांड बिहार के विकसित करने संबंधी कार्यक्रमों का विभिन्न माध्यमों द्वारा प्रचार-प्रसार कराया जाना एवं उनका समुचित उपयोग किया जाना।
- (iii) उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभाग अंतर्गत सोसाइटी/एजेन्सी गठित कर नवीन तकनीक के माध्यम से दायित्वों को निर्वहन करना।
- (iv) विज्ञापनों को लक्षित वर्ग तक प्रभावकारी ढंग से पहुंचाना, सरकारी विज्ञापनों हेतु पात्रा निर्धारित करना, सरकारी विज्ञापन की स्वीकृति, निर्गम, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, भुगतान की प्रक्रिया निर्धारित करना एवं विज्ञापनों का पद in house design की व्यवस्था करना।
- (v) कार्यपालिका नियमावली के अनुपालनार्थ समय-समय पर आवश्यक आदेश निर्गत करना एवं निर्गत विज्ञापनों की भुगतान व्यवस्था को सरल एवं पारदर्शी बनाना।
- (vi) सरकारी कार्यक्रमों/नीतियों एवं संदेशों के बेहतर एवं प्रभावकारी प्रचार-प्रसार हेतु व्यवस्था विकसित करना एवं मीडिया के Approach एवं Attitude का अनुश्रवण की व्यवस्था एवं प्रक्रिया विकसित करना।

4. परिभाषाएं :- इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

- (i) 'समाचार पत्र' से अभिप्रेत है ऐसे समाचार पत्र जो प्रेस और पुस्तक अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत हो।
- (ii) 'समाचार पत्रिका' से अभिप्रेत है ऐसे समाचार पत्रिका जिनका साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक तथा वार्षिक प्रकाशन होता हो एवं जो प्रेस और पुस्तक अधिनियम, 1867 के प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा पंजीकृत हो।
- (iii) 'विभिन्न माध्यमों' से अभिप्रेत है समाचार पत्र/पत्रिका/स्मारिका/गृह-पत्रिका/विज्ञान पत्रिका, फिल्म पत्रिका, खेल पत्रिका, कला, साहित्य, सांस्कृतिक पत्रिका सहित समसामयिक पत्रिका/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सेटलाईट चैनल/केबुल चैनल/रेडियो/वेबसाइट/सोशल मीडिया/मोबाइल ऐप्स/एस0एम0एस0 सहित विज्ञापन कार्य हेतु रेलवे स्टेशन/बस स्टैण्ड/मॉल/हवाई अड्डा / मेट्रो स्टेशन / ट्रेन / मूवीज थियेटर/ प्रचार वाहन/पम्पलेट/पोस्टर/ब्रोसर/कॉफी टेबुल बुक/कॉन्क्लेव जिसे विभाग द्वारा विशेष अभियान/प्रयोजन के अवसर पर मीडिया, संस्था अथवा संस्थान के साथ संयुक्त भागीदारी में अथवा स्वतंत्र रूप से चलाये जाने वाले अभियान विशेष का प्रचार-प्रसार हेतु माध्यम सहित इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले बोर्ड/अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण/होर्डिंग/पलैक्स/दिवाल लेखन/प्रदर्शनी/गीत नाट्य/नुक्कड़ नाटक आदि माध्यम।
- (iv) 'सचिव' से अभिप्रेत है प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग।
- (v) 'निदेशक' से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग।
- (vi) 'प्राधिकृत समिति' से अभिप्रेत है 'विज्ञापन प्राधिकृत समिति'।
- (vii) 'दर निर्धारण समिति' से अभिप्रेत है विभिन्न माध्यमों से विज्ञापन के प्रचार-प्रसार के दर निर्धारण हेतु गठित समिति।
- (viii) डी0ए0वी0पी0 से अभिप्रेत है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का 'विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय'।
- (ix) 'पंजीयक' से अभिप्रेत है 'भारत सरकार के समाचार पत्रों के पंजीयक'।
- (x) 'ए0बी0सी0' से अभिप्रेत है 'ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन'।
- (xi) 'उपक्रम' से अभिप्रेत है 'बिहार सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले सभी बोर्ड/निकाय/निगम/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/समिति' / **प्राधिकार।**
- (xii) 'बिहार संवाद' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग अंतर्गत गठित 'बिहार संवाद समिति'।

- (xiii) 'वृत्तचित्र' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार कार्य एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु निर्मित किये जाने वाले वृत्तचित्र।
- (xiv) 'फिल्म' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार कार्य एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु निर्मित किये जाने वाले फिल्म।
- (xv) 'विज्ञापन' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा सरकार के विभिन्न विभागों एवं **सरकारी** उपक्रमों से प्राप्त होने वाला विज्ञापन, कार्यक्रम एवं उपलब्धि के लोक शिक्षण एवं लोक संवाद संबंधी कार्यक्रम के प्रचार-प्रसार / जागरूकता / अभियान से संबंधित विज्ञापन सामग्री का निर्माण एवं विभिन्न माध्यमों से प्रचार-प्रसार कार्य।
- (xvi) 'रेडियो चैनल' से अभिप्रेत है- रेडियो / सामुदायिक रेडियो / एफएम चैनल।
- (xvii) 'सेटेलाइट चैनल' से अभिप्रेत है- इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वैसे सेटेलाइट चैनल जिनका प्रसारण टेलीविजन / अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर होता है।
- (xviii) 'वेबसाइट' से अभिप्रेत है इन्टरनेट वेबसाइट / पोर्टल / सोशल मीडिया।
- (xix) 'मोबाइल ऐप्स' से अभिप्रेत है मोबाइल सॉफ्टवेयर एवं इन्टरनेट आधारित प्रचार-प्रसार हेतु माध्यम।
- (xx) 'एस0एम0एस0' से अभिप्रेत है मोबाइल द्वारा सूचना के प्रचार-प्रसार का माध्यम।
- (xxi) **'स्वीकृत सूची' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा संधारित विज्ञापन निर्गम हेतु स्वीकृत सूची।**
- (xxii) 'केबुल टी0वी0' से अभिप्रेत है सैटेलाइट चैनलों से प्राप्त सिग्नल को एम0एस0ओ0 के माध्यम से केबुल द्वारा टी0वी0 पर प्रसारण।
- (xxiii) 'विभाग' से अभिप्रेत है 'सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग'।
- (xxiv) 'वर्गीकृत विज्ञापन' से अभिप्रेत है नियुक्ति, निविदा, निलामी, नोटिस एवं अन्य घोषणाएं, जो एक विशेष शीर्षक के तहत समाचार पत्रों में प्रकाशित हों।
- (xxv) 'डिस्प्ले विज्ञापन' से अभिप्रेत है मास कम्पेन, कार्यक्रम, मुख्य नीति, उपलब्धि, नई योजनाओं की घोषणाएं तथा सामाजिक-आर्थिक एवं एतिहासिक मुद्दों, राष्ट्रीय पर्व, त्योहारों एवं राष्ट्रीय एवं राजकीय समारोहों एवं महान विभूतियों के स्मृति दिवसों आदि पर आधारित विषय-वस्तु का आकर्षक ढंग से प्रचार-प्रसार।
- (xxvi) 'डी0ए0वी0पी0 दर' से अभिप्रेत है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के 'विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय' द्वारा निर्धारित दर।
- (xxvii) 'विभागीय दर' से अभिप्रेत है किसी विज्ञापन को निर्गम करने हेतु **विभाग** द्वारा निर्धारित दर।

5. विभिन्न माध्यमों की स्वीकृत सूची

- (1) सरकारी विज्ञापन का निर्गम समाचार पत्र-पत्रिका तथा अन्य विभिन्न माध्यमों को वित्तीय सहायता देने के दृष्टिकोण से नहीं किया जाएगा। विज्ञापन के उद्देश्यों की पूर्ति एवं लक्षित समूह के मद्देनजर समाचार-पत्र-पत्रिका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया / केबुल टी0वी0 के चैनलों, रेडियो / एफएम0 रेडियो / सामुदायिक रेडियो चैनल, इन्टरनेट वेबसाइट / सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों को निर्धारित पात्रता एवं प्रावधान के आधार पर विज्ञापन प्राधिकृत समिति की अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत सूची में शामिल किया जा सकेगा।
- (2) स्वीकृत सूची में शामिल होने की अनिवार्य पात्रता रखने के बावजूद उक्त माध्यमों को स्वीकृत सूची में शामिल किया जाना समिति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। स्वीकृत सूची में शामिल होने हेतु पात्रता का निर्धारण विभाग कर सकेगा।
- (3) समाचार पत्र / पत्रिकाओं के वर्गीकरण, उनके मुद्रण क्षेत्र, प्रसार की जांच / सत्यापन एवं सूचीबद्धता अवधि का निर्धारण विभाग कर सकेगा।

6. स्वीकृत सूची से निष्कासन एवं राशि का आहरण

कोई समाचार पत्र / पत्रिका स्वीकृत सूची से विज्ञापन प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर विभाग द्वारा 12 महीने तक के लिए तत्काल प्रभाव से निष्कासित की जा सकेगी, यदि :-

- (i) प्रसार संख्या के संबंध में जान-बूझकर गलत सूचना / सूचनाएं देता हो अन्यथाय अथवा
- (ii) प्रकाशन में अनियमितता पाये जाने, पीरियोडिसिटी या शीर्षक में परिवर्तन करने अथवा बिना किसी पूर्व सूचना के प्रेस स्थल में परिवर्तन पाये जाने अथवा;
- (iii) आर0एन0आई0 का वार्षिक रिटर्न जमा नहीं करने या निर्धारित एजेन्सी से वार्षिक सर्कुलेशन प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त करने अथवा;
- (iv) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या अमर्यादित कार्यकलापों में लिप्त पाये जाने अथवा उक्त गतिविधियों में न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये जाने अथवा;
- (v) बिहार सरकार के विभिन्न विभागों एवं उनके अधीनस्थ उपक्रम आदि के निगमित विज्ञापन को दो अथवा दो से अधिक बार प्रकाशित नहीं करने और प्रकाशन से इन्कार करने पर।

उपरोक्त कंडिका (i), (ii) एवं (iii) की स्थिति में विभाग द्वारा संबंधित समाचार पत्र/पत्रिकाओं को भुगतान की गई पूर्व की राशि आहरित की जा सकेगी। राशि के आहरण तक उन्हें कोई विज्ञापन प्राप्त नहीं होगा।

7. विज्ञापन प्राधिकृत समिति

- (1) निधारित पात्रता रखने वाले प्रचार-प्रसार के विभिन्न माध्यमों को स्वीकृत सूची में शामिल करने हेतु एक विज्ञापन प्राधिकृत समिति होगी, जो आवश्यकता, व्यवहारिकता एवं राज्यहित को ध्यान में रखते हुए, आवेदन देने वाले विभिन्न माध्यमों को स्वीकृत सूची में सूचीबद्ध करने हेतु अनुशंसा कर सकेगी। इस समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग एवं प्रधान सचिव/सचिव, गृह विभाग द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (संयुक्त सचिव से अन्यून), अपर महानिदेशक/महानिदेशक, विशेष शाखा द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी (आरक्षी अधीक्षक से अन्यून), वित्त विभाग के एक प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव से अन्यून) निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग सदस्य एवं विज्ञापन शाखा के प्रभारी पदाधिकारी सदस्य-सचिव होंगे।
- (2) विभिन्न माध्यम, जो स्वीकृत सूची में शामिल होने की अनिवार्य पात्रता रखते हैं, को स्वीकृत सूची में शामिल किया जाना समिति के लिए बाध्यकारी नहीं होगा। कंडिका-6 के आधार पर स्वीकृत सूची में शामिल विभिन्न माध्यमों को, राज्यहित/कार्यहित में, स्वीकृत सूची से बाहर करने के लिए प्राधिकृत समिति स्वतंत्र एवं सक्षम होगी। प्रचार-प्रसार के वैसे माध्यम जिन्हें 'विभागीय दर' प्राप्त नहीं है उन माध्यमों हेतु दर निर्धारण समिति द्वारा अनुशंसित विभागीय दर पर विज्ञापन निर्गम हेतु समिति विचारोपरान्त अनुशंसा कर सकेगी।

8. दर निर्धारण समिति

वैसे समाचार पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रॉनिक चैनल/केबुल चैनल/रेडियो/सोशल मीडिया/वेबसाइट सहित अन्य विभिन्न माध्यमों द्वारा राज्यहित एवं जनहित में विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित कराने हेतु एवं स्वीकृत सूची में शामिल करने के पूर्व विभाग ऐसे प्रचार-प्रसार के माध्यमों के लिए 'विभागीय दर' का निर्धारण कर सकेगा, जिसके लिए एक दर निर्धारण समिति होगी, जो विज्ञापन का लक्षित वर्ग तक पहुँच, प्राथमिकता, आवश्यकता, उद्देश्यों की प्राप्ति एवं डी0ए0बी0पी0 दर आदि को ध्यान में रखते हुए राज्यहित एवं लोकहित में दर निर्धारण हेतु अनुशंसा करेगी। विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्धारित 'विभागीय दर' अधिकतम एक वर्ष के लिए ही मान्य होगा, जिसे प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्धारित किया जा सकेगा। इस समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग होंगे तथा निदेशक, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, वित्त विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) तथा गृह विभाग के प्रतिनिधि (उप सचिव से अन्यून) सदस्य एवं उप निदेशक/प्रभारी पदाधिकारी विज्ञापन, सदस्य-सचिव होंगे।

9. विज्ञापन दर-

- (1) विभिन्न माध्यमों यथा समाचार पत्र/पत्रिका/इलेक्ट्रॉनिक चैनल/केबुल चैनल/रेडियो/सोशल मीडिया/वेबसाइट आदि के माध्यम से विज्ञापन के प्रकाशन/प्रसारण हेतु हेतु विभागीय दर का निर्धारण दर निर्धारण समिति के अनुशंसा पर की जायेगी।
- (2) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग स्वीकृत सूची के समाचार पत्र/पत्रिका या अन्य प्रकाशनों को 'विभागीय दर' पर नियमित विज्ञापन निर्गम करेगा। विज्ञापन सामग्री तैयार कर विभिन्न माध्यमों को निर्गम होने की स्थिति में सभी प्रकार के विज्ञापनों के निधारित दर पर 15 प्रतिशत (डी0ए0बी0पी0 द्वारा निर्धारित दर) छुट(Discout) विभाग या विभाग द्वारा गठित सोसाईटी/एजेन्सी को अनुमान्य होगी।
- (3) विशेष परिस्थिति, प्रयोजन, अवसर अथवा अभियान अंतर्गत अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार-प्रसार हेतु 'विभिन्न माध्यमों', जिसका कोई विभागीय दर न हो तथा राज्य सरकार की स्वीकृत सूची में शामिल नहीं हो, लेकिन राज्यहित में उक्त माध्यम से सरकार विज्ञापन प्रकाशित/प्रसारित कराना चाहती है तो दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' एवं विज्ञापन प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर अवधि अथवा अंक विशेष/अभियान विशेष के लिए, राज्यहित एवं कार्यहित में विज्ञापन दिया जा सकेगा। ऐसे विज्ञापनों के निर्गम एवं भुगतान के लिए पात्रता एवं प्रक्रिया का निर्धारण विभाग करेगा।
- (4) विशेष परिस्थिति, अभियान एवं कार्यक्रम विशेष के अवसर पर लोकहित एवं राज्यहित में स्वीकृत सूची में शामिल विभिन्न माध्यमों के लिए राज्य सरकार अलग से दर निर्धारित कर सकेगी।

10. विज्ञापन निर्गम एवं भुगतान

- (1) बिहार सरकार के समस्त विज्ञापन निर्गम एवं भुगतान कार्य, बिहार सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़ने वाले परिनियत निकाय/निगमों/लोक उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/प्राधिकारों/समितियों आदि सहित केवल न्यायपालिका को छोड़कर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में केन्द्रीकृत रहेगा।
- (2) बिहार सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण में पड़नेवाले परिनियत निकाय/निगमों/लोक उपक्रमों/प्रतिष्ठानों/समितियों का दायित्व होगा कि वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही उक्त कार्यालयों/उपक्रमों द्वारा विज्ञापन मद में कर्णांकित राशि सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा इस प्रयोजन हेतु विशेष रूप से संधारित बैंक खाता में जमा करायेंगे। उनके द्वारा जमा की गयी राशि से

उक्त कार्यालय/उपक्रम के अध्यायना के आलोक में सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा प्रकाशित कराये गये विज्ञापन का भुगतान विभाग करेगा।

11. ग्लोबल विज्ञापन

सरकार के विभिन्न विभागों/उपक्रमों को ग्लोबल विज्ञापन की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में वे समाचार पत्र/पत्रिका/चैनल/वेबसाईट एवं अन्य माध्यम का उल्लेख करते हुए विज्ञापन सामग्री विभाग को न्यूनतम चालीस दिन पूर्व सुलभ करायेंगे। प्रस्तावित बिहार विज्ञापन नीति, 2016 की कंडिका-8 में गठित दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित 'विभागीय दर' एवं प्राधिकृत समिति की अनुशंसा पर सक्षम प्राधिकार के आदेश से विज्ञापन निर्गम किया जा सकेगा, जिसका भुगतान उस माध्यम के लिए निर्धारित 'विभागीय दर' पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया जायेगा।

12. लोक संवाद एवं ब्राण्ड बिहार तथा सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी प्रचार-प्रसार की व्यवस्था

- (1) विशेष अवसर/प्रयोजन/अभियान के दौरान बिहार सरकार के विभिन्न विभागों की उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार तथा बिहार की कला-संस्कृति एवं धरोहरों को राज्य एवं राज्य के बाहर आम जनता के बीच प्रचारित करने हेतु कॉफी टेबुल बुक एवं अन्य पुस्तकों का प्रकाशन विभाग करा सकेगा।
- (2) विभिन्न जनोपयोगी कार्यक्रमों/योजनाओं के प्रचार-प्रसार हेतु विभाग अभियान/कॉन्क्लेव/कार्यशाला आयोजित कर सकेगा तथा आवश्यकतानुसार अन्य प्रचार-प्रसार के माध्यमों यथा: टी0वी0 चैनल, समाचार पत्र समूह या अन्य संस्थाओं की सहभागिता से अथवा उनके सहयोगी के रूप में भी उक्त कार्यक्रम करा सकेगा।
- (3) गैर-स्वीकृत सूची के विभिन्न माध्यमों, ग्लोबल विज्ञापन, होर्डिंग, दीवाल-लेखन, प्रदर्शनी, गीत नाट्य, नुक्कड़-नाटक /पम्पलेट/ब्रोसर/ पोस्टर/बुकलेट/प्रचार वाहन आदि के माध्यम से जागरूकता/ प्रचार-प्रसार एवं सोशल मीडिया अंतर्गत फेसबुक, ट्वीटर, यू-ट्यूब/मोबाईल एप्स/एस0एम0एस0 एवं अन्य माध्यमों से सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार प्रभावकारी ढंग से विभाग द्वारा कराया जा सकेगा।

13. सरकार एवं जनता के बीच संवाद की स्थापना-

विभिन्न मुद्दों पर लोगों का मूड, परसेप्शन, फीड बैक को जानना-समझना, उनकी प्रतिक्रिया एवं अनुक्रिया प्राप्त करना, और मीडिया में प्रकाशित एवं प्रसारित समाचारों का विश्लेषण कर, आवश्यकतानुसार, सरकारी पक्ष/दृष्टिकोण को त्वरित ढंग से मीडिया के माध्यम से आम लोगों के बीच प्रस्तुत करने की व्यवस्था विभाग स्वयं या बिहार संवाद के माध्यम से करा सकेगा।

14. फेसिलिटेटर के रूप में बिहार संवाद के माध्यम से विज्ञापन कार्य हेतु संसाधन प्राप्त किया जाना-

- (1) विभाग द्वारा विज्ञापन प्राप्ति, निर्गम एवं भुगतान की प्रक्रिया को ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाने एवं विज्ञापन सामग्री के डिजाईन एवं कम्पोजिंग हेतु फेसिलिटेटर के रूप में बिहार संवाद के माध्यम से आवश्यकतानुसार संसाधन एवं सहयोग प्राप्त कर सकेगा अथवा आवश्यकतानुसार विभाग बिहार संवाद के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों/बोर्ड/ निगम आदि के वर्गीकृत एवं सजावटी विज्ञापनों का क्रियेटिव डिजाईन एवं सामग्री का निर्माण/वर्गीकृत डिजाईन एवं निविदा का कम्पोजिंग विकसित कराते हुए समाचार पत्रों को निर्गमन हेतु उपलब्ध करा सकेगा एवं इसके एवज में विभाग बिहार संवाद को निर्धारित शुल्क अनुमान्य होगा।
- (2) आधुनिक परिवेश के अनुरूप सूचना तकनीक का उपयोग सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार कार्य हेतु फेसिलिटेटर के रूप में बिहार संवाद के माध्यम से भी करा सकेगा।

15. विज्ञापनदाता को समाचार पत्रों की आपूर्ति

- (1) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा समाचार पत्र/पत्रिकाओं को निर्गत विज्ञापन के विरुद्ध प्रकाशित विज्ञापनों से संबंधित समाचार की प्रति निगर्मादेश में दिये गये पते पर विज्ञापनदाता को सुलभ कराना होगा तथा सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को भी उसकी प्रति मुहैया करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर संबंधित विज्ञापन का भुगतान देय नहीं होगा।
- (2) किसी निगर्मादेश के विरुद्ध संबंधित विज्ञापन का प्रकाशन नहीं किये जाने स्थिति में समाचार पत्रों को 48 घंटे के अन्दर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा।

16. बिना निर्गमादेश के विज्ञापन का प्रकाशन

कोई माध्यम सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत निगर्मादेश के बिना विज्ञापन का प्रकाशन नहीं करेगा।

17. विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा निर्गत निगर्मादेश में अंकित तिथि को विज्ञापन का प्रकाशन करना होगा। निगर्मादेश में अंकित तिथि के अलावे अन्य तिथियों को विज्ञापन का प्रकाशन कराया जाने की स्थिति में यदि विलम्ब से विज्ञापन प्रकाशन से विज्ञापन के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हुई प्रतीत हो, वैसी स्थिति में तत्संबंधी विज्ञापन का भुगतान नहीं किया जा सकेगा।

18. सजावटी/डिस्ले विज्ञापन

- (i) सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग न केवल सरकार के विभाग एवं उनके अधीनस्थ विभिन्न निगम/निकाय/समिति/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/प्राधिकार आदि के विज्ञापनों (वर्गीकृत, डिस्ले आदि) को निर्गम करेगा बल्कि उन विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु समाचार पत्र/पत्रिकाओं के चयन, विज्ञापन हेतु स्थान निर्धारित/आरक्षित करने का भी कार्य करेगा। विज्ञापनों के निर्गम हेतु समाचार पत्र/पत्रिकाओं के चयन में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।
- (ii) विज्ञापन का डिजाईन एवं विषयवस्तु/सामग्री निविदादाता को नियमानुसार प्रकाशन तिथि से पूर्व तैयार कराकर भेजनी होगी। किसी विभाग एवं उनके अधीनस्थ विभिन्न निगम/निकाय/समिति/लोक उपक्रम/प्रतिष्ठान/प्राधिकार आदि से प्राप्त विज्ञापनों के आकार एवं उसके डिजाईन में परिवर्तन, संशोधन करने का अधिकार तथा विभाग की उपलब्धियों आदि से संबंधित सजावटी विज्ञापन तैयार कर प्रकाशित कराने एवं भुगतान करने का अधिकार सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग का होगा। जिन विज्ञापनों को प्रमुखता दी जानी हो, वैसे विज्ञापनों को सूचना एवं जन-सम्पर्क द्वारा उसे 'डिस्ले विज्ञापन' में परिवर्तित किया जा सकेगा।
- (iii) महत्वपूर्ण अवसरों/विशेष आयोजनों यथा: स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बिहार दिवस, प्रमुख पर्व/उत्सव/ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जयंती/शहादत दिवस, राज्य सरकार की नीति, कार्यक्रम एवं उपलब्धियों पर आधारित डिस्ले विज्ञापनों के प्रकाशन हेतु विभाग स्वयं अपनी ओर से भी विज्ञापन निर्गम कर सकेगा।
- (iv) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आमजनों के लोक शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण तिथियों, अवसरों, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार हेतु आयोजित होने वाले अभियानों के शुभारंभ संबंधी विज्ञापनों का प्रकाशन सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग करा सकेगा। साथ ही, महत्वपूर्ण परियोजनाओं के शिलान्यास/उद्घाटन समारोहों से संबंधित डिस्ले विज्ञापन का प्रकाशन भी विभाग करा सकेगा।
- (v) विभिन्न अवसरों पर महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्रियों के संदेश संबंधी डिस्ले का प्रकाशन विभाग करा सकेगा।

19. समाचार पत्रों का चयन

विज्ञापन सामग्री प्राप्ति के बाद विज्ञापन की प्रकृति, प्राक्कलित राशि आदि के आधार पर लक्षित समूह को ध्यान में रखते हुए, सक्षम प्राधिकार द्वारा विज्ञापन हेतु समाचार पत्रों का चयन किया जायेगा। समाचार पत्रों का चयन हो जाने पर, उसके प्रकाशन पर होने वाले व्यय की स्वीकृति भी उसी सक्षम स्तर से दी जायेगी एवं उसे प्रकाशन हेतु समाचार पत्रों को निर्गत किया जायेगा। विज्ञापनों के निर्गम हेतु समाचार पत्र/पत्रों के चयन में विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

20. स्वीकृत सूची में शामिल होने 'विभागीय दर' एवं डी0एवी0पी0 दर प्राप्त होना विज्ञापन प्राप्त करने का आधार नहीं—

विभिन्न माध्यमों को स्वीकृत सूची में शामिल होने, विभागीय दर एवं डी0एवी0पी0 दर प्राप्त होने मात्र से विज्ञापन प्राप्त करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इन्हें विभाग द्वारा प्रकाशन/प्रसारण/प्रदर्शन की आवश्यकता/लक्षित जन समूह/क्षेत्र तथा मितव्ययिता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए विज्ञापन दिया जा सकेगा।

21. आधुनिक परिवेश के अनुरूप सूचना तकनीक का उपयोग सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रचार-प्रसार एवं ब्रांड बिहार को विकसित करने हेतु पेशेवर एजेंसी की सेवा प्राप्त करना एवं प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार कार्य हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेशेवर, दक्ष एवं कुशल एजेंसी/कर्मियों की सेवा प्राप्त करना—

- (1) विभिन्न माध्यमों हेतु विज्ञापन सामग्री का निर्माण विभाग विभागीय दर पर स्वयं/बिहार संवाद के माध्यम से विभाग करा सकेगा।
- (2) आधुनिक परिवेश के अनुरूप सूचना तकनीक का उपयोग ब्रांड बिहार विकसित करने, सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं उपलब्धियों का लोक शिक्षण हेतु प्रभावकारी ढंग से प्रचार-प्रसार कार्य करने हेतु आउटसोर्सिंग के माध्यम से पेशेवर, दक्ष एवं कुशल एजेंसी/कर्मियों की सेवा विभाग प्राप्त कर सकेगा और इस कार्य के एवज में निर्धारित शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

22. सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग का सुदृढीकरण —

बिहार विज्ञापन नीति, 2016 के सम्यक कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए विभाग का विज्ञापन संकाय/प्रभाग तथा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का आधारभूत संरचना को सुदृढ करते हुए नई सूचना तकनीक के उपकरणों और कर्मियों से सुसज्जित किया जा सकेगा।

23. माध्यमों की सूचीबद्धता एवं विभागीय दर का वार्षिक पुनरीक्षण —

विभिन्न माध्यमों की स्वीकृत सूची की वार्षिक पुनरीक्षण प्राधिकृत समिति के माध्यम से एवं विभिन्न माध्यमों के विभागीय दर का वार्षिक पुनरीक्षण दर निर्धारण समिति के माध्यम से करा सकेगा।

24. विज्ञापन निर्गम हेतु वित्तीय शक्तियों का निर्धारण –

विज्ञापन निर्गम के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन संबंधी विनियमों का निर्धारण विभाग करेगा। उक्त वित्तीय शक्तियों को आवश्यकतानुसार वित्त विभाग की सहमति से विभाग द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।

25. विज्ञापन नियमावली का गठन

- (1) विज्ञापन की इस नीति के सम्यक् क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग विज्ञापन नियमावली बना सकेगा।
- (2) विभाग समय-समय पर इस नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा एवं आवश्यकतानुसार संशोधन करा सकेगा।

26. अन्यान्य

- (1) विज्ञापन की इस नीति के द्वारा इससे पूर्व निर्गत इस विषय पर सभी संबंधित आदेश/अनुदेश/नीति अवक्रमित समझे जाएंगे। ऐसे आदेश/अनुदेश/नीति के अवक्रमण के होते हुए भी उक्त आदेशों/अनुदेशों/नीतियों द्वारा, या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई इस नीति के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों यह नीति उस दिन प्रवृत्त थी, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।
- (2) विभाग द्वारा पूर्व की स्वीकृत सूची में शामिल किये गये विभिन्न माध्यमों को अगले आदेश तक सूचीबद्ध मानते हुए विभाग दर निर्धारण समिति के माध्यम से, विज्ञापन हेतु विभागीय दर निर्धारित कर सकेगा।

27. बिहार विज्ञापन नीति-2016 में वित्त विभाग, गृह विभाग, विधि विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाए और उसकी प्रति सभी संबद्ध विभागों/विभागाध्यक्षों को भेजी जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ब्रजेश मेहरोत्रा,
सरकार के प्रधान सचिव।

No. विज्ञा0(4)01-02/2016-01/ I&PRD

The 12th September 2016

Bihar Advertisement Policy, 2016

Subject :-Approval of Bihar Advertisement Policy, 2016

Preamble-As per provisions in Bihar Executive Rules and Bihar Advertisement Policy, 2008, Information & Public Relations Department has been made responsible to publicize the classified advertisement, tender, information & other content based on the programs & achievements of various Department and Corporation/Body/Society/Public Enterprises/ Establishment /Authority under State Government in the form of advertisements on Akashwani, Television, Newspaper/ Magazine, Electronic Media, Internet etc. and important Newspaper/ Magazine of national & international repute, too and has also been entrusted to ensure centralized monitoring and make payment for it.

In the light of ever changing circumstances, emergence of new information techniques, changing environment of work and procedures, to understand and get feedback on the mood and perception of the common citizen on various issues along with getting their reaction and response to various programs of the government; to ensure dissemination and propagation of government programmes, schemes and achievements for public awareness and education, establish effective public dialogue and to develop **Brand Bihar** by professional use of various modern techniques of mass media; use of social media viz. facebook, twitter, YouTube and outdoor publicity including other mediums for effectively publicizing and disseminating information through advertisements; formation of a society for the purpose of developing creative and for fulfillment of other objectives and financial delegation etc., there is a need for certain amendment in existing provisions and inclusion of certain new provisions in Bihar Advertisement Policy 2008. Under present circumstances, Advertisement Policy in new shape seems to be essential for the discharge of departmental responsibilities.

Therefore, "**Bihar Advertisement Policy, 2016**" is constituted under the Information & Public Relations Department, Government of Bihar by superseding the clause and rules of the existing Advertisement Policy.

2.

- (1) This policy shall be called "**Bihar Advertisement Policy, 2016**"
- (2) This policy shall come into force from the date of issue of the notification.

3. Objectives

- (i) To understand the mood, perception feedback of the common people on various issues, receive their reactions & responses, and by analyzing the news published in media and to make arrangement for placing the stand/views of the government quickly through media among general public as per need.
- (ii) To publicize the policies/programs/achievements of government for the mass education, establish effective public dialogue and to publicize the programmes related to development of "Brand Bihar" through various media and it's proper utilization.
- (iii) To form society/agency, under the department for the fulfillment of objectives, discharge of responsibilities by new technique.
- (iv) To effectively disseminate the advertisements to the target group, set the eligibility criteria for the release of Government advertisements, determine the processes /systems for the approval, mode of payment and delegation of financial powers and make arrangement for the development of In- house design of Government advertisements.
- (v) To issue appropriate directions from time to time to ensure compliance of the rules of executive business and make the process of payment of released advertisement simple and transparent.
- (vi) To develop system for the proper and effective dissemination of government programmes/policies, messages and to develop system for procedure and monitoring of the Approach & Attitude of media.

4. Definition – In these policy, unless there is anything otherwise in subject or context-

- (i) "Newspaper" means "such newspapers which are registered by the Registrar of newspaper, under the provisions of Press & Books Act, 1867 of Government of India".
- (ii) "News Magazine " means "such New Magazine" which are registered by the Registrar of newspaper , Government of India" under the provisions of Press & Books Act, 1867, published Weekly, Fortnightly, Monthly, Tri-monthly, Half-yearly and yearly.
- (iii) "Various Media" means News paper/Magazine/Electronic media's satellite channel/ Cable channel/ Radio/ Website/ Social media/ Mobile apps/SMS, including railway station for advertisement/bus stand/ mall/airport/ metro station/ train/ movies theater/publicity van/ pamphlet/ poster/brochure/ electronic display board/ other electronic gadgets/ hoarding/flax/ wall painting/ exhibition/ songs play/ street play and other media.
- (iv) "Secretary" means "Principal Secretary/Secretary Information & Public Relations Department".
- (v) "Director" means "Director Information & Public Relations Department".
- (vi) "Empowered Committee" means "Advertisement Empowered Committee" constituted under Rule 5.

- (vii) "Rate Fixation Committee" means "committee constituted for the fixation of rate of advertisement for different media" under Rule 6.
- (viii) "DAVP" means "Directorate of Advertisement and Visual Publications of the Ministry of Information & Broadcasting, under Government of India".
- (ix) "Registrars" means "Registrar of Newspaper of G.O.I".
- (x) "A.B.C." means "Audit Beaur of Circulation".
- (xi) "Undertaking" means "All Board/ Body/ Corporation/ Public Enterprises/ Society under the ownership & control of "Government of Bihar".
- (xii) "Bihar Samwad" means "Bihar Samwad Samiti constituted under Information & Public Relations Department" under society Registration Act, 1860".
- (xiii) "Documentary" means "documentary produced for the advertising work and development of "Brand Bihar" by Information & Public Relations Department".
- (xiv) "Film" means "film produced for the advertising work and development of "Brand Bihar" by Information & Public Relations Department".
- (xv) "Advertisements" means the advertisement received from different department and government undertakings, development of advertising material and its publicity through various medium about programmes and achievements for public awareness and public dialogue including awareness by Information & Public Relations Department".
- (xvi) "Radio Channel" means "Radio/Community Radio/FM channels".
- (xvii) "Satellite Channel" means "those satellite channel which telecast, through the Television/other electronic media".
- (xviii) "Website" means "Internet Website/Portal/Social Media".
- (xix) "Mobile Apps" means "media for publicity, based on mobile software and internet".
- (xx) "SMS" means "mode of publicity of information by mobile".
- (xxi) "Approved list" means "Approved List of state government for the release of advertisement, maintained by Information & Public Relations Department".
- (xxii) "Cable T.V." means "Telecast on T.V., the signals, received from satellite channel through M.S.O. by Cable".
- (xxiii) "Department" means "Information & Public Relations Department".
- (xxiv) "Classified Advertisement" means "Recruitment, Tender, Notice and other declarations which are published under special Title in different newspapers".
- (xxv) "Display Advertisement" means "Dissemination of the material based on topics of mass-campaign, programme, important policy, achievement, announcement of new policy and historical and socio-economic topics in an attractive manner".
- (xxvi) "DAVP Rate" means "Rate fixed by DAVP under Information & Broadcasting Ministry, government of India".
- (xxvii) "Departmental Rate" means "Rate fixed by Rate Fixation Committee to released any advertisement"

5. Approved list of various media

- (i) The release of government advertisement to the newspaper-magazine and other various media will not be given for the purpose to extend the financial assistance. Newspaper/ Magazine/ Electronics Media/Cable TV Channels/ Radio/F.M. Radio/Community Radio Channel/ Internet Website/Social Media and other media may be included in Approved List on the recommendation of Advertisement Empowered Committee on the basis of prescribed eligibility and provisions, for the fulfillment of the objectives of the advertisement and targeted group.

- (ii) In spite of requisite eligibility criteria for the inclusion in Approved List, it will not be binding upon the Information & Public Relations Department to include those media in Approved List. Department would determine the eligibility criteria for the inclusion in Approved List.
- (iii) The classification of Newspapers/Magazines, its printing area, scrutiny/verification of the circulation and determination of the period of listing would be done by the department.

6. Expulsion from the approved list and withdrawal-

Any empanelled media can be expelled from approved list by the department for twelve months with immediate effects on the recommendation of Advertisement Empowerment Committee if

- (i) found to have deliberately submitted false information regarding circulation or otherwise; or
- (ii) found to have discontinued its publication, changed its periodicity or its title or have become irregular or changed its premises/press without due intimation; or
- (iii) it has failed to submit its Annual Return to the Registrar Newspaper of India (RNI) or its Annual Circulation Certificate from the prescribed agencies; or
- (iv) indulged in unethical practices or anti national activities and has been indicted by court of law for such activities; or
- (v) it refuses to accept and carry an advertisement issued by the various departments and their undertaking on more than two occasions.

In case of aforesaid para (i) (ii) & (iii), the payment done earlier to the concerned media could be withdrawn by the department. Till such withdrawal, no advertisement shall be released to it.

7. Advertisement Empowered Committee-

- (1) There will be an Advertisement Empowered Committee, which would recommend on application for the inclusion of various media in approved list for publicity, having requisite eligibility, considering the requirement, practicality and interest of state. The chairman of this committee be Principal Secretary/Secretary, Information & Public Relations Department, an Officer (not below the rank of Joint Secretary) authorized by Principal Secretary/Secretary, Home Department., an Officer (not below the rank of Superintendent of Police) authorized by A.D.G. / D.G., of Special Branch, a representative of Finance Department (not below the rank of Joint Secretary), Director, Information & Public Relations Department as a member and Officer In-charge, Advertisement, shall be Member- Secretary of the committee.
- (2) It will not be binding upon the committee to include, those various media in the approved list, having requisite eligibility to be included in the approved list. The Empowered Committee will be independent and competent to expel different media from approved list in the interest of state/work, as per clause-6. The committee after due consideration may recommend release of advertisement for those media who at present do not have any departmental rate after the recommendation of the Rate Fixation Committee.

8. Rate Fixation Committee -

For the publicity of advertisement in newspapers, magazines, electronic channel, cable channel, radio, social media, website etc. including various media in the interest of state and public interest and for those various media before their inclusion in the approved

list, department can determine the departmental rate, for which there will be a Rate Fixation Committee who recommend the rates in the light of the access and reach of the said advertisement to the targeted group, its priority, requirement, the achievement of the goals and the DAVP rate etc. in the interest of the state and public interest. After the approval of the department, fixed rate will be valid for a maximum period of one year which can be revised/reviewed every year. The chairman of this committee shall be Principal Secretary/Secretary, Information & Public Relations Department and Director, Information & Public Relations Department, a representative (not below the rank of Deputy Secretary) of Finance Department, a representative (not below the rank of Deputy Secretary) of Home Department, be member and Deputy Director/Officer In-charge, Advertisement, shall be Member- Secretary of the committee.

9. Advertisement Rate-

- (1). The departmental Rate for the publication /circulation of advertisement through various medium, such as Newspaper/Magazine/Electronic Channel /Cable Channel/Radio/ Social Media/Website, etc will be fixed on the recommendation of Rate Fixation Committee.
- (2). Information & Public Relations Department may release advertisement well ordered at the departmental rate to those newspaper/magazine or other media which are in the approved list., 15% (Rate fixed by Directorate of Advertisement and Visual Publications) discount shall be admissible on the rate fixed for all kinds of advertisement to department or society/agency constituted under the department, in case of release of prepared advertisement material to various mediums.
- (3). In special circumstances, purpose, occasion or special campaigns, advertisements can also be issued in public and state interest to non empanelled media of international and national repute and do not have departmental rate, but in such cases if the state governments wants to advertise in such media then it can be done for a special period, special issue or full campaign after fixation of the department rate by the Rate Fixation Committee and recommendation of the Empowered Committee. The department may determine eligibility and procedure for payment and release of such advertisement.
- (4). Under special circumstances, campaign or on occasion of specific programme in the public and state interest, the Government may fix separate rate for the various media included in the approved list.

10. Release of Advertisement and Payment-

- (1). All works pertaining to release and payment of government advertisements, including Local Bodies/Corporation/Public Enterprises/Establishments/ Authority/ Societies etc., under the ownership and control of Bihar Government, excluding only the Judiciary, will be centralized under the Information and Public Relations Department.
- (2). It will be responsibility of Local Bodies/Corporation/Public Enterprises/ Establishments/ Authority/ Societies etc., under the ownership and control of Bihar Government, to deposit the earmarked amount for their advertisement in the Bank Account maintained especially for this purpose under Information & Public Relations Department in beginning of the financial year. The department may make payment against the fund deposited by said offices/undertakings for the advertisement published by Information & Public Relations Department on their requisition.

11. Global Advertisement-

The Global Advertisement is required by various Departments/ Undertakings of the government. Under such circumstances they will provide advertising material and the name of the newspaper/ magazine/channel/ website and other media, to the department, forty days in advance. The advertisements could be released after the approval of the competent authority, on the recommendation of Empowered Committee at the departmental rate fixed by Rate Fixation Committee under clause-8 of Bihar Advertisement Policy, 2016. The payment will be made to that media on fixed departmental rate and the procedure fixed by the department.

12. Management of effective publicity of Public dialogue, Brand Bihar and Government policies, programmes, schemes and achievements for mass education-

- (i) For publicizing the achievements of various departments, the culture and heritage of Bihar; the department can publish coffee table books and other books/ printable material for circulation among common people, within and outside the state during special occasions/purpose/campaigns.
- (ii) For the publicity of various programs and schemes useful for public, the department can arrange conclaves and workshops on its own and as per requirement, can also arrange for such conclaves and workshops in collaboration or in association with other mediums of publicity, such as TV channels, newspaper houses and other institutions.
- (iii) Non empanelled various mediums, global advertizing, hoarding, wall writing, exhibition, Song and drama, street plays, pamphlet, brochure, poster, booklet, publicity vans etc. including social media such as face book/twitter/YouTube/mobile app/SMS/and others, can also be used for publicity of achievements, policies, schemes and programmes of Government for mass education in an effective manner as per established norms and procedures.

13. Government- Public Dialogue-

Department, by itself or through "Bihar Samwad" can develop suitable mechanism and infrastructure to understand the mood, perception and get feedback of the general public on various issues, to receive their reaction & response, after analyzing the news published/broadcast in media and arrange quick response to place the views of the government on these issues and educate the masses about the facts of the case.

14. To obtain resources of "Bihar Samwad" as a facilitator for advertising work-

- (i) The department can utilize, as per need, the resources of Bihar Samvad Society as a facilitator for making the process of receipt, release and payment of advertisement on line and transparent; as per need the department can also use these resources of Bihar Samvad for development and design of classified and creative advertisement, tender composing of advertisement of different departments and Local Bodies/Corporations/ PSUs/Authorities/ Societies for release to the newspaper/magazines and various media against which the department will pay fix fees to the "Bihar Samwad".
- (ii) Publicity of Government policy, programme, plan and achievement of the Government for mass education may also be done by "Bihar Samwad" as a facilitator, in an effective manner by using Information technology, according to modern environment.

15. Supply of newspaper to client advertiser-

- i. Every newspaper will have an obligation to send one copy each of the newspaper on their own, carrying advertisements issued through Information & Public Relations Department to the client at the address mentioned in the Release Order and also to Information & Public Relations Department, failing to which payment for the advertisement may not be considered.
- ii. It will be mandatory for newspapers to inform Information & Public Relations Department within 48 hours, if they have not been able to publish the advertisement on the due date.

16. Publication of advertisement without release order-

No newspaper will publish advertisement without receipt of the relevant Release Order by the Information & Public Relations Department.

17. Date of publication of the advertisement-

The newspaper will be obliged to strictly adhere to the date of publication of advertisements as given in the Release Order. Publication of advertisement on dates other than that given in the Release Order will not be accepted and no payment for that advertisement shall be made, if it is found that such publication does not fulfill the objectives of the advertisement.

18. Decorative/Display advertisement-

- i. Information & Public Relations Department would not only, release advertisement (classified, display etc) of government department and various corporations/body/board/public enterprises/establishment/authority under it, but also do the role for selection of newspaper/ magazine and fixation/reservation of space for for the publication of that advertisement. The decision of the department in selection of Newspaper/Magazine for the release of advertisement shall be final.
- ii. The design of advertisement and content/material would be sent by the advertiser prior the date of publication. The right to modify and change the design and size of the advertisement, received from various departments/ corporation/ body/ society/ public enterprises/ establishment/authority and to get published decorative advertisement after designing related to the achievements of the department and its payment will be vested to the Information & Public Relations Department. Such advertisement may be changed to "Display Advertisement", which has to be highlighted by the Information & Public Relations Department as per need and priority.
- iii. Department, on its own may release display and creative advertisements for the publication on the important occasions/special events, such as Independence Day, Republic Day, Bihar Diwas, important festivals/birthdays /martyr day of legendry personalities/important policies, programmes, schemes and achievements of the government.
- iv. Information & Public Relations Department may release advertisements whenever required on the special occasions related to inaugurations of schemes, programmes, policies, important campaigns of the Government for mass education.
- v. Department may publish display messages of H.E Governor, Hon'ble Chief Minister & Hon'ble Ministers on specific occasions.

19. Selection of News Papers –

After receipt of the advertising material, the selection of news papers for the advertisement will be done by the competent authority on the basis of the nature of

advertisement, estimated amount, considering the targeted group. The sanctioning of the expenditure to be incurred on its publication, after the selection of news paper will be accorded by the same competent level and it will be released to the newspaper for publication. The decision of department in the selection of news paper/ papers for the release of advertisement shall be final.

20. Inclusion in Approved list, Departmental and DAVP rate is not the basis of getting advertisement –

Mere inclusion in approved list and having departmental and DAVP rate for various mediums, shall not be construed as right to obtain the advertisement. The advertisement shall be released to them considering the need of the publication/ circulation/ exhibitions/ targeted group/ area and thriftiness.

21. Use of modern information techniques for publicity of the policies/programmes/ schemes/achievement of the Government for mass education and getting services of professionals, experts and competent agency to develop "Brand Bihar" through outsourcing in effective manner-

- i. Department on its own or through Bihar Samwad may develop advertising material for various media at departmental rate.
- ii In order to develop "Brand Bihar" by using information techniques, as per modern environment and to publicize the programmes, policies, schemes achievements for mass education in an effective manner through professionals, experts and service of competent agencies would be taken by the department through outsourcing and the department would make payment of fixed requisite fees for this work.

22. Strengthening of the Information & Public Relations Department:-

To ensure proper implementation of the "Bihar Advertisement policy, 2016", the department shall endeavor to strengthen the infrastructure of the advertisement wing/section of the department and its field offices with modern and new information technology and equipment along with procuring the services of the expert personnel/agency through outsourcing.

23. Annual review of listing of media and the departmental rate -

Department may annually review the approved list of various media through the Empowered Committee and annually review the departmental rate of various media by Rate Fixation Committee.

24. Determination of Financial Power for release of the advertisement –

Department may frame the regulations for the delegation of financial power for release of advertisement. As per requirement, said financial power would be amended by the department with the consent of Finance Department.

25. Formation of Advertisement Rules-

- (i) To ensure the proper execution of this advertisement Policy, Information & Public Relations Department would frame Advertisement Rules.
- (ii) The Department shall review the execution of this policy time to time and as per requirement, may amend it accordingly.

26. Miscellaneous-

- (i) With the coming into force of these Advertisement Policy, all orders, directions issued on this subject in the past stands repealed. Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken in the exercise of any power conferred by or under the said orders, directions shall be deemed to have been done or taken in the exercise of the powers conferred by or under these

rules as if this policy was in force on the day on which such thing or action was done or taken.

- (ii) The department may decide the departmental rate from a fixed date, through the Rate Fixation Committee for various media which are already in the approved list prior to coming into effect of all this new policy. Till the new departmental rates come into effect the old rates will be applicable.

27. The concurrence of the Finance Department, Home Department, Law Department, and approval of the Cabinet for the Bihar Advertisement Policy' 2016 has been obtained.

Order- It is ordered that a copy of this resolution be published in the issue of Bihar Gazette (extraordinary) for the information to the public and its copy be sent to all concerned department/ Head of Departments.

By order of the Governor,
BRIJESH MEHROTRA,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 754-571+5000-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>